महानगरीय गांवों में जल संकट

डॉ. राकेश राणा

यदि वर्षा का जल समुचित ढंग से संचयन किया जाए तो भूजल का स्तर भी बना रहेगा और अतिरिक्त जल बहकर घाटियों और पास की नदियों में चला जाएगा जिससे नदी और छोटे जल स्रोत भी पानीदार हो जाएंगे और बहाव का पैटर्न भी सामान्य बना रहेगा। और यह तभी संभव है जब बारिश का पानी जहां गिरे वहीं रोक लिया जाए। 'शहर का पानी शहर में, खेत का पानी खेत में' के मॉडल पर पानी का समुचित संचय हो।

जल एक प्राकृतिक संसाधन तो है ही उससे अधिक यह मानवीय संसाधन है क्योंकि इससे मानवीय अस्तित्व जुड़ा है। जल, सांस और भोजन की तरह बुनियादी और जीवंत आवश्यकता है। विडंबना यह है कि पृथ्वी पर मानव जीवन की पुर्नसंरचना के संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि आधुनिक मनुष्य ने जीवन के आधारभूत तत्व को ही पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। औद्योगिकता की अति और उससे होने वाले प्रदूषण, बड़े बांधों का निर्माण और उससे होने वाला विस्थापन, पानी पर गर्माती राजनीति और उससे होने वाले जल स्रोतों के बंटवारे तथा पानी को बाजार की वस्तु बनाना और इस सार्वजनिक संपदा का निजीकरण, मानवीय अस्तित्व के संकट और जीवन क्षरण के कारण बन रहे हैं। यदि जीवन सब कुछ से पानी नहीं बनाया जा सकता। इसे कभी नहीं बनाया जा सकता। इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। इसलिए आज अगर मानवीय चिन्ता का प्राथमिक बिन्दु जल संरक्षण नहीं बनता तो हम जीवन द्रोही होंगे। हमारे शरीर में भी केवल खून ही नही बल्कि दो हिस्से तो पानी ही है। शरीर के भीतर पानी होने के लिए आवश्यक है कि बाहर उससे भी अधिक पानी हो। क्योंकि जल सिर्फ जलचरों के लिए ही नहीं होता बल्कि थल चरों, नभ चरों और यहां तक कि अचरों के लिए भी आवश्यक है। पानी चर-अचर सब कुछ है। एक तरल और गतिशील जीवन का नाम ही पानी है। पानी से ही जीवन के गुणसूत्र हैं। इसलिए जल ही जीवन है।

हमने एक महानगरीय जीवन में जल के महत्व को समझने की दृष्टि से दिल्ली के एक नगरीय गांव शाहपुर जट का अध्ययन किया क्योंकि दिल्ली की एक धनी और बड़ी आबादी दिल्ली के ऐसे ही करीब 300 गांव में रहती है। अब सवाल उठता है कि नगरीय गांव किसे कहे? किसी भी समुदाय का आकार और उसकी जनसंख्या का घनत्व वहां के लोगों के व्यवहार में जल इतना अनिवार्य है तो जल में जीवन अवश्य होता होगा। अब तो यह वैज्ञानिक शोधों ने भी सिद्ध कर दिया है कि जल में जीवन होता है (डॉ. मसारूइमोटो)। जल (H_2O) की संरचना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हुई है। लेकिन क्या इस ज्ञानमात्र से इसे बनाया जा सकता है। पानी की असली सामर्थ्य यही है कि पानी से सब कुछ बनता है किन्तु

बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करती महिलाएं

प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं। किसी भी समुदाय की श्रेणी का निर्धारण उसकी जनसंख्या का आधार, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और वहां की सामाजिक संरचना और मूल्य व्यवस्था के आधार पर किया जा सकता है। नगरों में आबादी जैसे-जैसे विजातीय स्वरूप लेती जाती है उसमें धीरे-धीरे कई वर्ग पनपने लगते हैं और परिणामस्वरूप नई प्रकार की अन्तःक्रियाएं जन्म लेती हैं। द्वितीय समूह बनने लगते हैं तथा औपचारिक व्यवस्था आकार पाने लगती है। ये सभी उसे नगरीय बनावट प्रदान करते हैं। किसी नगरीय गांव में परंपरागत सामाजिक संरचना व मूल्यों का प्रभाव वहां पर आने वाले बाहरी लोगों पर भी पड़ता है और इन अप्रवासियों का प्रभाव वहां की संपूर्ण सामाजिक संरचना पर भी दिखाई देता है। इसमें अलग-अलग अवधि के अप्रवासियों, मकानों के निजी स्वामित्व के अलग-अलग प्रतिमान निवास संबंधी आर्थिक परिवर्तन, व्यवस्थागत कृषि कार्यों में लगना आदि। वहीं जाति तथा धार्मिक समूहों का अलग-अलग पड़ोस के रूप में एक साथ रहना बताता है कि द्वितीय और तृतीय नातेदारों से बने संयुक्त परिवारों का आधिक्य इन जगहों पर पाया जाता है। अनजानापन तथा व्यक्तिवादिता व्यक्तियों व समूहों की निरंतर गतिशीलताओं का परिणाम है।

भारत में जो नगरीकरण हुआ वह कई तरह की विचित्रताएं लिए हुए है उसके विभिन्न प्रतिमान हैं। जहां तक एक नगरीय गांव का सवाल है उनमें कई प्रकार की विचित्र अवस्थाएं उत्पन्न हुई। कहीं-कहीं तो गांव में नगर उठ खड़े हुए है जैसे दिल्ली के कुछ गांव में, भिलाई और दुर्गापुर के कुछ गांव में। विकास की सारी प्रक्रिया में जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र विकसित हुए वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण संरचना वाले क्षेत्र रह गए हैं। अध्ययन बताते हैं कि नगरीकरण के विकास के साथ पारस्परिक संबंध, पारिवारिक व्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था परिवर्तित होती जा रही है।

विश्व में 1.1 अरब लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। वर्ल्ड वॉटर फेडरेशन का अनुमान है कि विश्व में 12000 क्यूबिक कि.मी. पानी प्रदूषित हो चुका है। पानी की असमान उपलब्धता इसी से स्पष्ट है कि एक अमेरिकी नागरिक प्रतिदिन 600 लीटर पानी का उपभोग करता है और एक यूरोपीय नागरिक 300 लीटर प्रतिदिन, वहीं एक एशियाई और अफ्रीकी मूल का नागरिक प्रतिदिन 10-15 ली. पानी का उपभोग कर पाता है। इस अध्ययन से सामने आया है कि दिल्ली में पानी के उपयोग की व्यवस्था कितनी अन्यायपूर्ण और असमान है। दक्षिणी दिल्ली के ही कुछ गांव में पानी की उपलब्धता 28 ली./व्यक्ति प्रतिदिन तक सीमित है जबकि दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में 510 ली./व्यक्ति प्रतिदिन तक की उपलब्धता का सरकारी आंकड़ा असमान वितरण वाली अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिचायक है। लगभग 20 गुना का यह अंतर समाज के आम और खास वर्गों में जलापूर्ति और उनकी जीवन गुणवत्ता को दर्शाता है।

बढ़ती आबादी के कारण महानगरों में गहराता जल संकट

पेयजल की कमी के कारण प्रदूषित जल पीने के लिए बाध्य लोग

वहीं भारत के विभिन्न हिस्सों में शहर और गांव की व्यवसायिक संरचना एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में दो तरह के ग्रामीण क्षेत्र मौजूद हैं एक तो वे जो बहुत प्राचीन बसे हुए हैं, दूसरे वे जो बहुत नए हैं। प्राचीन गांव में भी दो तरह के गांव है। एक तो वे जो विकसित होते शहर के अंदर ही रह गए और घिर गए हैं लेकिन अपनी संरचना को समाप्त नहीं कर पाए। दूसरे वे जो शहर के बाहर या सीमांत पर हैं। गांव की जाति आधारित परंपरागत व्यवसायिक संरचना अब आधुनिक व्यवसायिक सरंचना से स्थानांतरित हो रही है।

राजधानी दिल्ली में पानी की स्थिति

बरसात का पानी बहकर कई नदी नालों के जरिए यमुना में जाकर मिलता है। घरों से निकला पानी प्रतिदिन उसी वर्षा के पानी के साथ बहकर बसंत कुंज से निकलकर सिटी और डिफेंस कॉलोनी से गुजरता हुआ राष्ट्रपति भवन के पीछे से आकर बारापुला के नीचे से गुजरते हुए यमुना में मिलता है। छोटे-बड़े करीब 17 नाले यमुना में गिरते हैं। वजीराबाद में यमुना का पानी लगभग पूरी तरह बांध लिया जाता है उसके नीचे यमुना में सिर्फ गंदा पानी ही बहता है। दिल्ली में बरसाती पानी कोही से नीचे नालों के माध्यम से बह जाता है या फिर खादर और डाबर इलाकों में जमा हो जाता है। यहीं पानी फिर भूजल के रूप में प्रकट होता है जिसको कुओं के द्वारा नांगलोई, महरौली, नजफगढ़ और शाहदरा प्रखण्डों में ट्यूबवेल के द्वारा निकाल कर उपयोग में लाया जाता है। बाकी क्षेत्रों में वजीराबाद से यमुना के पानी को पाइप लाइन के द्वारा भेजा जाता है। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में भी भूजल है। पहले शहर का

विस्तार रिज और यमुना के मध्य था। जैसे-जैसे शहर का विस्तार रिज को पार कर पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ता गया वहां का दूषित पानी भी नजफगढ़ नाले से होता हुआ वजीराबाद के ऊपर यमुना में आकर गिरने लगा जिससे पानी लगातार दूषित होता चला जा रहा है।

वास्तव में दिल्ली में जल संकट कुप्रबंधन का परिणाम है। यह मानव निर्मित है न की प्राकृतिक। कुछ आवश्यकता से अधिक उपभोग कर रहे हैं तो कुछ की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। समस्या को उल्टा करके देखा जाता है। हरदम सप्लाई बढ़ाने की बात होती है जबकि दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत भी नहीं है। आए दिन जल विवाद पर पड़ोसी राज्यों की धमकियां आम बात हैं। पानी के निजीकरण से वितरण में और ज्यादा असमानता आएगी। अमीरों का उपभोग बढ़ेगा और गरीबों का घटेगा जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता सीधे तौर पर प्रभावित होगी।

यह अध्ययन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण जिले का है। जो एक नगरीय गांव "शाहपुर जट" के जल संकट के विशेष संदर्भ में है। अध्ययन के लिए इस क्षेत्र का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि जल संकट की दृष्टि से दिल्ली का दक्षिणी जिला सबसे अधिक त्रस्त है। यह दिल्ली का ऊंचा एरिया है जहां भूजल स्तर भी काफी नीचे है और पानी वितरण की सार्वजनिक व्यवस्था भी सर्वाधिक लचर है। दक्षिण दिल्ली के महरौली गांव में गत वर्षों में जल की सबसे कम उपलब्धता रही है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन को जल संकट के विभिन्न कारणों, परिणामों और प्रभावों की दृष्टि में दक्षिण दिल्ली के एक नगरीय गांव पर केंद्रित किया गया और उन्हें समझने के प्रयासों के साथ ही इस क्षेत्र में जल संकट के संभावित समाधानों को भी खोजने की दिशा में तथ्य जुटाने के प्रयास किए गए हैं।

नगरीय गांव 'शाहपुर जट' के विभिन्न हिस्सों के 162 परिवारों से जल से जुड़े आंकड़े लिए गए। अध्ययन के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार से जल संबंधी सामान्य सूचनाएं एकत्रित की गयी। परिवार के एक व्यक्ति का सघन साक्षात्कार किया गया। विभिन्न सूचनाओं को साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्र किया गया। दूसरे चरण में ग्रामीणों से समूह चर्चाएं और औपचारिक-अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से जल संकट के कारणों को समझने का प्रयास रहा। संपूर्ण क्षेत्र-कार्य (*Field Work*) के दौरान अवलोकन को एक अतिरिक्त अध्ययन विधि के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक जल व्यवस्था की आधारभूत संरचना, पाइप लाइन का विस्तार, अवैध कनेक्शनों की स्थिति, लीकेज एवं अन्य स्थितियों का जायजा लिया गया। तृतीय चरण में गांव के प्राचीन जल स्रोतों, तालाबों, जोहड़ों, कुओं के बारे में गांव के बुजुर्गों से जानने का प्रयास किया गया।

दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जट गांव में जल के दैनिक उपयोग की स्थिति

क्रमांक	पानी का इस्तेमाल (बाल्टी में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	0-10	17	10.49
2.	10 -20	62	38.27
3.	20 - 30	37	22.84
4.	30 - 40	20	12.34
5.	40 से ऊपर	12	7.40
6.	नहीं पता	14	8.64
	योग	162	100

नोट : अधिक उपयोग करने वाले लोग सरकारी जलापूर्ति के अतिरिक्त पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं।

नगरीय गांव के निवासियों द्वारा जल के उपयोग और दुरूपयोग की बात तो तब आती है जब उन्हें पर्याप्त जलापूर्ति होती हो। दक्षिण दिल्ली के महरौली गांव में प्रतिदिन मात्र 20 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जलापूर्ति होती है। वहीं दिल्ली के पॉश एरिया छावनी क्षेत्र में 510 लीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन की जलापूर्ति है। दिल्ली जल बोर्ड के इस आंकड़े से ही स्पष्ट है कि दिल्ली में कौन पानी का उपयोग करता है और कौन दुरूपयोग? इससे स्पष्ट है कि कौन पानी का संकट झेलता है और कौन पानी से खेलता है? सूचना दाताओं ने 30 से 60 मिनट प्रतिदिन पानी आने की बात स्वीकार की। 59 प्रतिशत सूचनादाता आधे घंटे से एक घंटे तक पानी आपूर्ति बताने वाले पाए गए। वहीं आधे घंटे से भी कम आपूर्ति वाले लोग भी कम नहीं थे ऐसे लोगों का प्रतिशत 27.7 प्रतिशत तक पाया गया। मात्र 3.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डेढ़ घंटे तक पानी आने की सूचना प्रदान की। 24 घंटे में मात्र आधे से एक घंटे पानी की आपूर्ति होना किसी भी स्तर पर मानकों के अनुरूप नहीं है जल आपूर्ति के समय से ही जल संकट का पता चल जाता है जबकि यह नगरीय ग्रामीण बसाहट दिल्ली के पॉश हिस्से दक्षिणी दिल्ली में है और उसके चारों ओर प्रथम क्षेत्रों की कॉलोनियां हैं (हौज खास, पंचशील, एशियाड विलेज क्लब आदि है)।

तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीणों द्वारा पानी का उपयोग प्रतिदिन कितनी बाल्टी परिवार के स्तर पर किया जा रहा है या जरूरी है। प्राप्त तथ्यों से सामने आया कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने दिनभर में दस से बीस बॉल्टी पानी उपयोग की बात स्वीकार की। ऐसा कहने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक 38.2 प्रतिशत था वही 22.8 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जो 20-30 बाल्टियां तक उपयोग

दिल्ली में जल संकट का दृश्य

करते थे। 12.3 प्रतिशत सहभागियों ने 30-40 बाल्टियों के उपयोग की बात कही। मात्र 12 परिवार ऐसे थे जो 40 से ऊपर बाल्टियों को इस्तेमाल करते थे। लगभग इतने ही उत्तरदाताओं ने अंदाजा न होने की बात कहीं। दिल्ली के नगरीय गांवों में, जहां अधिकांश मध्यम आकार के और संयुक्त प्रकार के परिवारों का आधिक्य है, वहां लगभग 40 प्रतिशत परिवारों को 10-20 बाल्टी पानी उपलब्ध होना मानकों के कहीं तक भी अनुरूप नहीं है। वही 10 प्रतिशत परिवारों को दस बाल्टी से कम पानी उपलब्ध है। मात्र 23 प्रतिशत परिवार 20-30 बाल्टी पानी का उपभोग करते हैं। मात्र 12 प्रतिशत परिवार 30-40 बाल्टी इस्तेमाल कर पाते हैं। 2 परिवार ऐसे थे जो 40 बाल्टी से ऊपर पानी इस्तेमाल कर रहे थे।

दिल्ली के विस्तार और विकास में ये नगरीय गांव जरिया जरूर बने हैं पर विकास के हर मास्टर प्लान में ये उपेक्षित होते गए। सरकारी नीतियों की ये उपेक्षा ही इन गांवों में आधारभूत संकटों का मुख्य कारण बनी। दक्षिणी दिल्ली के शाहपुरजट गांव में जल संकट के कारणों की पड़ताल करने के दौरान पाया गया कि 40.7 प्रतिशत ग्रामीणों के लिए पानी मुख्य समस्या बना हुआ है। वहीं 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पानी+सीवर+बिजली को वरीयता क्रम में मुख्य समस्या के तौर पर स्वीकारा है। सफाई को समस्या बताने वालों का प्रतिशत मात्र 6 था। वहीं तीन प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए गांव में कोई भी समस्या नहीं थी। वास्तव में नगरीय गांवों के लिए 'जल संकट' ही मुख्य समस्या है और उससे उनकी अधिकांश समस्याएं जुड़ी हैं। सीवर समस्या भी कहीं न कहीं पानी की कमी के कारण ही उत्पन्न होती है। बिजली व सफाई उनके जीवन में पानी से बहुत बाद में महत्व रखती है। अतः पानी की कमी बड़ी समस्या है। मजबूत आर्थिक स्थिति वाले लोग तो पानी खरीदकर या सामूहिक टैंकर मंगवाकर उस कमी को पूरा कर लेते हैं और अपने उपभोग का सूचकांक नीचे नहीं गिरने देते हैं। जलापूर्ति में कमी कमजोर आर्थिक स्थिति और गरीब लोगों, मजदूरों तथा बाहरी लोगों के लिए इन बसाहटों में बड़ी और गंभीर समस्या है। महानगरों की तरफ रोजगार की तलाश में लोगों का अधिक संख्या में आना तथा दूसरी ओर महानगर के उपेक्षित पिछड़े इलाकों में आधारभूत संरचना का कमजोर होना बड़ा कारण है। जहां 46.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जनसंख्या के दबाव को जल संकट की मुख्य वजह बताया, वहीं 25 प्रतिशत सहभागियों ने पानी वितरण की असमानता को मुख्य कारण बताया। 11.8 सूचनादाताओं ने अवैध कनेक्शनों को पानी संकट के लिए जिम्मेदार बताया और 17.3 प्रतिशत ने पाइपों से पानी लीकेज को जल संकट की जड़ बताया। इन गांवों में लगातार बढ़ती बाहरी आबादी इस संकट को बढ़ा रही है। पानी वितरण की असमानता तो जग जाहिर कारण है ही।

दिल्ली के नगरीय गांव में जल संकट के परिणामों की परिणिति विभिन्न रूपों में सामने आ रही है। आए दिन दिल्ली के अखबार जल संकट की स्थितियों से उत्पन्न परिणामों जल विवादों, लड़ाई-झगड़ों, आपसी प्रतिस्पर्धा, जलचोरी और सीना जोरी के समाचारों से भरे रहते हैं। जहां तक शाहपुरजट गांव में जल संकट के परिणामों का सवाल है तो अध्ययन के दौरान अनेक बार अनौपचारिक बातचीत में यह उभरकर सामने आया कि इस गंभीर समस्या को ग्रामीण स्थानीय कारकों का परिणाम मानते हैं। सर्वेक्षण के दौरान 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अवैध कनक्शनों को अपने क्षेत्र में जल संकट का कारण बताया। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण लोग जल संकट की इस उलझी हुई समस्या को अपने आस-पास की ही वजह मानते हैं जबकि यह उस संपूर्ण व्यवस्था के दोषों का परिणाम है जो जलापूर्ति के अन्यायपूर्ण वितरण से शुरू होती है। यहीं कुछ लोगों के द्वारा पानी के चोरी करने और अवैध कनेक्शनों के परिणाम के रूप में उभरकर सामने आता है। इसी के साथ जल संकट के

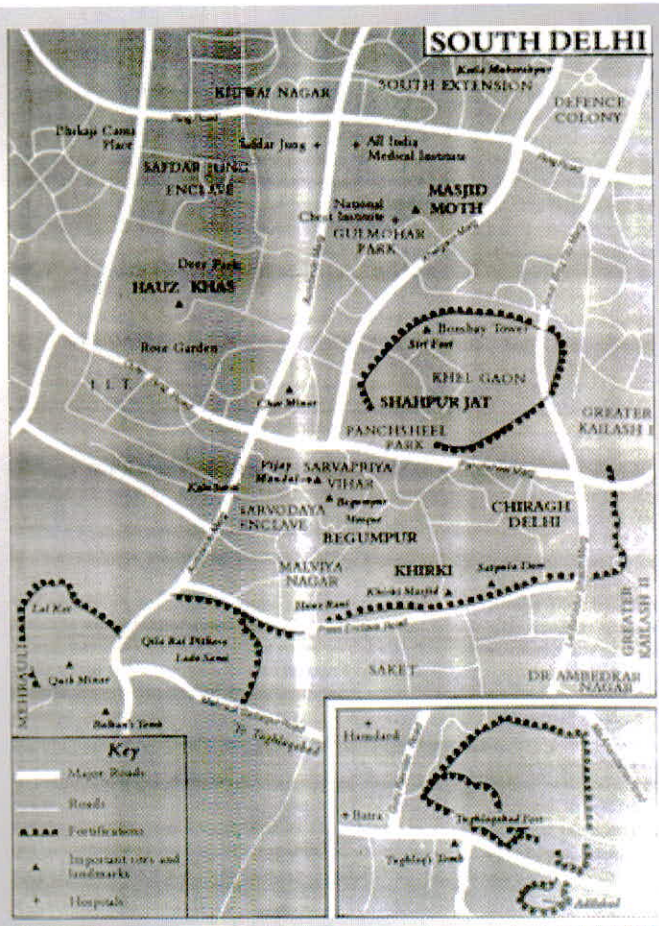

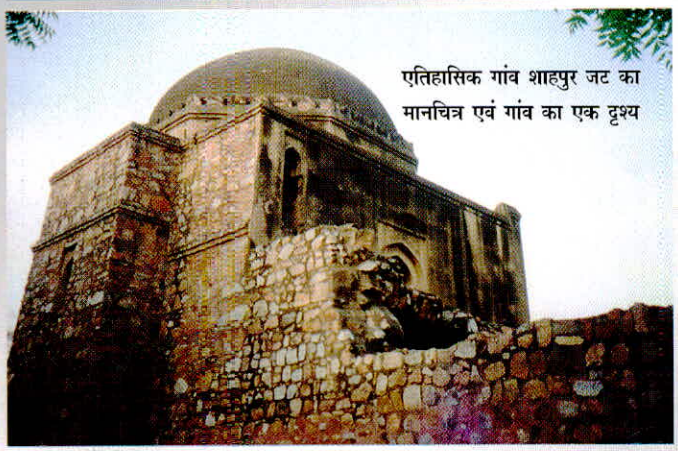

एतिहासिक गांव शाहपुर जट का मानचित्र एवं गांव का एक दृश्य

अनेक परिणाम समाज को भुगतने पड़ते हैं। आपस में बढ़ते तनाव, जलस्त्रोतों को लेकर झगड़े, ये सब जल संकट के परिणामों के रूप में समझे जा सकते हैं। इस गांव मे संयुक्त परिवार व्यवस्था बड़े स्तर पर मौजूद है और बड़े आकार के परिवारों की मौजूदगी इन गांवों में देखी गयी। आय के स्तर पर अधिकांश परिवार 5 से 10 हजार रुपए प्रतिमाह आय स्तर के ही हैं जिनके लिए पानी को खरीदकर इस्तेमाल करना सहज नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि कम जलापूर्ति के कारण और कम आय स्रोतों के कारण इस जल संकट का प्रभाव सीधा उनके जीवन पर पड़ता है तथा उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अनौपचारिक बातचीत में उभरकर आया कि कुछ परिवार मजबूरीवश जरूरी खर्चों में कटौती कर पानी को खरीदते हैं। बड़े परिवारों

की आय का एक बड़ा हिस्सा पानी संकट से उभरने में ही जाया हो जाता है। इन नगरीय गांव में जितना एकल परिवारों को पसंद किया जा रहा है (24 प्रतिशत) उससे अधिक प्रतिशत (24.7 प्रतिशत) अभी भी बड़े परिवारों को पसंद करने वाले वहां मौजूद हैं। अतः इन नगरीय गांवों में पारंपरिक परिवार व्यवस्था बहुत हद तक अपना आकार बचाए हुए है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि भारत में नगरीकरण की रफ्तार कितनी भी तेज हो अभी भी भारतीयों के लिए संयुक्त परिवार का आकर्षण बरकरार है। नगरीय गांव का यह अध्ययन बताता है कि लगभग दो तिहाई परिवार संयुक्त प्रकार के हैं या संयुक्त परिवार प्रणाली की तरह जी रहे हैं।

निष्कर्ष

- अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि सर्वाधिक सूचनादाता (59 प्रतिशत) ने पानी की कम समय सप्लाई (30-60 मिनट/दिन) की बात स्वीकार की जो जल संकट की गंभीर समस्या को इंगित करता है।
- अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि जहां 38.2 प्रतिशत व्यक्ति 10 से 20 बाल्टी पानी का उपयोग करते हैं, वहीं 7.40 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हे काफी मात्रा में पानी आपूर्ति होती है। पानी का यह असमान वितरण पानी की चोरी, अवैध कनेक्शनों और दंबगई के चलते होता है। गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं वे अधिक पानी कब्जा लेते हैं।
- गांव में सर्वाधिक प्रतिशत (72.2 प्रतिशत) संयुक्त परिवारों का पाया गया जो कि गांव के परंपरागत रहन-सहन को जीवंत बनाए हुए हैं। स्पष्ट है कि इन बड़े परिवारों में पानी की खपत ज्यादा होती होगी और आपूर्ति का समय कम होने की वजह से संकट स्वाभाविक है।
- गांव में जनसंख्या दबाव व पानी का असमान वितरण जल संकट का मुख्य कारण है। उत्तरदाताओं ने जल संकट में जनसंख्या आधिक्य की भूमिका 46.29 प्रतिशत व 24.69 प्रतिशत ने पानी वितरण की असमानता को जिम्मेदार ठहराया।
- गांव में 35.80 प्रतिशत लोग निम्न आय वाले थे जिनकी अधिकतर आय पानी पर ही खर्च हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि जल उपलब्धता में निम्न आय वर्ग वालों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- अधिकांश उत्तरदाता 31.48 प्रतिशत गांव में केवल अपनी पैतृक संपत्ति को संभाले हुए थे, कुछ पुरानी संपत्ति के किराये के लिए या किसी विशेष आयोजन अथवा घटना के दौरान गांव आते थे।
- सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि गांव का शैक्षिक स्तर बहुत ही कम था। 32.09 प्रतिशत हाईस्कूल व 25.30 प्रतिशत इंटर शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता थे जिससे पता चलता है कि अधिकांश ग्रामीण निम्न व मध्य स्तर तक ही शिक्षित थे और जल सकंट को दूर करने के उपायों से अनभिज्ञ।
- दैनिक समाचार पत्रों के अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में जल संकट को लेकर निरंतर पानी के समाचारों में वृद्धि हुई जो कि अप्रैल में 18.7 प्रतिशत व जून में 30 प्रतिशत तक हो गयी।
- दैनिक समाचार पत्रों के अध्ययन से पाया गया कि पानी को लेकर शिकायत/विरोध प्रर्दशन व झगड़े/रंजिश एवं दुघर्टनाओं के समाचार बड़े पैमाने पर स्थान पा रहे हैं।

अध्ययन से स्पष्ट है कि कहां जल का अभाव है और कहां जल का प्रभाव है और ऐसा क्यों है? देश की राजधानी में कौन पानी का उपयोग करता है, कौन इसके संकट को झेलता है और कौन पानी से खेलता है? यह पानी की प्रतिदिन आपूर्ति, उसकी उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता से स्पष्ट हो जाता है। विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण वाले इस शहरीकृत गांव चारों ओर से प्रथम श्रेणी की पॉश कॉलोनियों जैसे हौजखास, एशियाड विलेज, पंचशील जैसे समृद्व और संपन्न क्षेत्रों के बीच बसता है। इन आस-पास के इलाकों में जल सकंट के प्रत्यक्ष प्रभाव कभी देखने में नहीं आए जबकि गांव के लोगों की पानी के लिए लगी कतारें, टैंकरों के इर्द-गिर्द भीड़ और पानी को लेकर बाट जोहते ग्रामीण अक्सर देखे जाते हैं क्योंकि गांव में परंपरागत स्रोत लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। कुछ वृद्ध ग्रामीणों से पूछने पर सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि करीब दस कुएं गांव में मौजूद थे जो आज सभी मृतप्रायः हैं। न ही कोई जोहड़, पोखर या तालाब अब गांव में बचा है। जागरूकता और ज्ञान के अभाव के कारण अनपढ़ ग्रामीणों में वाटर हार्वेस्टिंग के आधुनिक तौर-तरीकों की भी समझ का अभाव है। इन सबका संयुक्त प्रभाव जल संकट के बड़े कारण के रूप में देखा जा सकता है। विकास की अंधी दौड़ में गांव कंक्रीट के जगंल की तरह फैल रहा है। विकास की सरकारी नीतियों में ये दिल्ली की ग्रामीण बसावटें लगातार उपेक्षित हैं जिन सबका परिणाम इस तरह के आधारभूत संकटों के रूप में सामने आ रहा है। इन्हीं का परिणाम है कि ग्रामीणों में रोज जल सकंट को लेकर लड़ाई-झगड़े, विवाद, अधिकाधिक जल भंडारण करने की स्पर्धा, पानी की चोरी, छोटे-छोटे कलह आम होते जा रहे हैं। घूस देकर पानी के कनेक्शनों की चोरी करना, अतिरिक्त पाइपलाइन डलवा लेना, टैंकरों को गलत ढंग से बेचना-खरीदना जैसे भ्रष्टाचार सब इसी का परिणाम है।

जागरूकता और ज्ञान के अभाव के कारण अनपढ़ ग्रामीणों में वाटर हार्वेस्टिंग के आधुनिक तौर-तरीकों की भी समझ का अभाव है। इन सबका संयुक्त प्रभाव जल सकंट के बड़े कारण के रूप में देखा जा सकता है। विकास की अंधी दौड़ में गांव कंक्रीट के जंगल की तरह फैल रहा है।

गत 50-60 वर्षों में दिल्ली में पानी की खपत तीन गुणा बढ़ी है। झुग्गियों, गांवों और पिछड़े इलाकों में मात्र 30 प्रतिशत ही पानी मिल पाता है। रिहायशी इलाकों में यह वितरण भरपूर है। पानी की कमी वाले इलाकों में पानी के टैंकरों द्वारा पानी भिजवाया जाता है। जिसके लिए 975 टैंकरों का सहारा लिया जाता है। जिनमें 575 टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के व 400 प्राइवेट हैं। एक टैंकर प्रतिदिन प्रति शिफ्ट 330 रूपए लेता है। इस प्रकार वर्ष के औसतन 35 करोड़ रूपए टैंकर पर व्यय होते हैं। सरकारी अनुमान बताते हैं कि पाइप द्वारा पानी पहुंचाने में 55 रूपए प्रति वर्ग मीटर खर्च आता है अतः वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में इस खर्च से पानी पहुंचाया जा सकता है।

जल संकट का समाधान जल संरक्षण, जल स्रोतों के विकास, संवर्द्धन और उचित प्रबंधन में छिपा है। उस प्रकृति पोषक जीवन शैली में उसका हल है जिसे बचपन से ही स्कूली शिक्षा और अनौपचारिक ढंग से संस्कार के तौर पर हर मनुष्य में रोपने की आवश्यकता है। जीवन में जल की महत्ता को समझने और समझाने की आवश्यकता है। महानगरीय जीवन में जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से संभव है। यदि वर्षा जल का समुचित ढंग से संचयन किया जाए तो भूजल का स्तर भी बना रहेगा और अतिरिक्त जल बहकर घाटियों और पास की नदियों में चला जाएगा जिससे नदी और छोटे जल स्रोत भी पानीदार हो जाएंगे और बहाव का पैटर्न भी सामान्य बना रहेगा और यह तभी संभव है जब

बारिश का पानी जहां गिरे वहीं रोक लिया जाए। 'शहर का पानी शहर में, खेत का पानी खेत में' के मॉडल पर पानी का समुचित संचय हो। वर्षा का पानी मानवीय आवश्यकताओं के लिए बड़ा वरदान है एक अजस्र स्रोत है। विश्व में जहां औसतन 87 सेमी. बारिश होती है वहीं भारत में वर्ष में औसतन 117 सेमी. बारिश होती है। दिल्ली की 500 किमी. लंबी सड़कों पर बहने वाले बरसाती पानी का संचय ही यदि दिल्ली वासी समुचित ढंग से कर लें तो वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके अपनाकर इस वर्षा जल का संचयन दिल्ली को जल संकट से चमत्कारिक ढंग से उबार सकता है। इसी के साथ नदी-नालों पर चेक डेम बनाकर जल को रोका जा सकता है तथा भूजल और स्थल जल के तमाम स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। गैर जरूरी कार्यों और जल के दुरुपयोग में कमी लाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार महानगरीय जीवन में जल संकट को छोटी-छोटी पहलों से दूर किया जा सकता है।

निष्कर्षतः देश की राजधानी दिल्ली आज जल सकंट की घोर चपेट में है जो अनेकों तकनीकी खामियों, ऑपरेशनल दिक्कतों और वित्तीय समस्याओं का परिणाम है। जल प्रबंधन की अकुशलता, वितरण प्रणाली का चुस्त-दुरुस्त न होना, भूजल दोहन के समय अधिकांश पानी का बर्बाद हो जाना और जलापूर्ति के दौरान पानी की एक बड़ी मात्रा लीकेज के रूप में बर्बाद हो जाना, भूजल स्तर का तीस से पचास मीटर तक नीचे चला जाना, तीव्र गति से बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और नगरीकरण का अंधाधुंध फैलाव जल संकट की जड़ हैं जो एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है और समय रहते समुचित समाधान की मांग कर रहा है।

संपर्क करें :

डॉ. राकेश राणा
असिस्टेंट प्रो. समाजशास्त्र,
पी.टी. जे.एन. पी.जी. कालेज,
बांदा, उत्तर प्रदेश

"बदलते परिवेश में जल संसाधन प्रबंधन की भूमिका"

विषय पर

पांचवीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी–2015

सितंबर 10–11, 2015

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की दिनांक 10–11 सितंबर, 2015 को "बदलते परिवेश में जल संसाधन प्रबंधन की भूमिका" विषय पर पांचवीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। हिंदी में आयोजित की जाने वाली इस संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न विषय वस्तुओं पर शोध पत्र आमंत्रित किए जाते है।

अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी संस्थान की वेबसाइट (**www.nih.ernet.in**) का अवलोकन कर सकते हैं।

.....संगोष्ठी संयोजक.....
रमा मेहता
रा.ज.सं.,रूड़की,
01332–249257, 249267
ईमेल प्रस्तुति
uniyalpk@gmail.com
pksharma019@gmail.com / pawan@nih.ernet.in